



विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि अगले 40 सालों तक प्रिय चॉकलेट गायब हो जाएगी क्योंकि कोको के पौधे गर्म जलवायु में जीवित रहने के लिए जुड़ा रहे हैं। ये पौधे सिर्फ 20 डिग्री तापमान में ही जीवित रह सकते हैं तथा भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में ये खुब फलते-फूलते हैं क्योंकि यहाँ नमी व वर्षा काफी ज्यादा है। पर आगामी 30 वर्षों में यहाँ लोबल वर्मिंग के कारण तापमान में 2.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी जिससे इनका अस्तित्व खतरों में पड़ जाएगा और इसका असर पूरी दुनिया में चॉकलेट उद्योग पर पड़ सकता है। यू.एस. नैशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि, तापमान बढ़ने से जमीन और पौधों का पानी सूख जाएगा और लोबल वर्मिंग की वजह से पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाने का भी खतरा है, इसलिए कोको के उत्पादन में कमी आने की पूरी संभावना है। तब ब्राजील व घाना जैसे देशों, जहाँ कोको का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, के समक्ष दुविधा यह होगी कि वे विश्व भर में कोको की आपूर्ति करे या कोको का अस्तित्व बचाए।

सोनिया गांधी ने ममता...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को अपनी पार्टी में लेकर, ममता ने विपक्ष को बाँटने का काम करने की गलत कोशिश की है, लेकिन राहुल ने वहाँ एकत्रित नेताओं से कहा कि वे ममता की इन कोशिशों को मामूली हरकत मानते हैं, इनकी अन्देशों को राहुल ने नेताओं से कहा कि कुछ नेताओं के तुणमूल में चले जाने से कैसे निपटना है यह सोनिया गांधी पर छोड़ दें।

रणनीतिक मीटिंग में भाग लेने वालों में ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड्गे, आनंद शर्मा, अर्धर रंजन चौधरी, के.सी. वेणुगोपाल, जयमर रमेश, के. सुरेश और रवनीत बिट्टू शामिल थे। मीटिंग से बाहर आए नेताओं ने बताया कि टी.एम.सी. विपक्ष के भीतर ही धौंस जमा सकती है, लेकिन ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार पर विपक्ष के हमले को तोषण करने में और अन्तर: टी.एम.सी. सांसदों की ममता बिग्रेड को इस हमले में शामिल होने के लिए वाध्य करने में शामिल होने के लिए विपक्ष पार्टी की भूमिका त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड्गे ने मीटिंग को बाद पत्रकारों को बताया कि नेताओं ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए 15-16 मुद्दों

का चयन किया है। इनमें प्रमुख हैं- कृषि कानून, मंहगाई और कोविड-19 से मरे लोगों के परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाना।

जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि ममता अधिक आक्रामक हो रही हैं तो उन्होंने कहा कि "जो लोग हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हम उनसे मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। क्या संसद के पूर्व सत्रों में ममता जी की टी.एम.सी. हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ी रही? कांग्रेस संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में कोविड-19 कुप्रबंधन, कोरोना क्षतिपूर्ति, मंहगाई और किसान आंदोलन के मुद्दों को मजबूती से उठाने की योजना बना रही है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में सोनिया ने पार्टी संगठन सचिव वेणुगोपाल को निर्देश दिए कि वे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहें कि वे कोविड-19 पीड़ितों को अधिक क्षतिपूर्ति दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार को लिखें।

आगामी 23 दिसम्बर तक चलने वाले संसद सत्र के दौरान दिल्ली में एक विशाल विरोध रैली आयोजित करने की संभावनाओं पर भी कांग्रेस नेताओं ने चर्चा की।

अब प्लेटफॉर्म टिकट फिर से 10 रु. का होगा

नई दिल्ली, 25 नवम्बर भारतीय रेलवे के यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के बड़े हुए दाम वापस लेने का फैसला किया है। अब प्लेटफॉर्म टिकट पहले की तरह ही 10 रुपये का

■ कोविड बढ़ने पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित करने के मकसद से सरकार ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 5 गुना बढ़ाकर 50 रु. कर दिया था।

लिखनऊ, 25 नवम्बर भारतीय किसान यूनियन (बी.के.यू.) के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है। टिकैत एक साल से अधिक समय से दिल्ली के गाजीपुर सीमा से अधिक किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि एम.एस.पी. से किसानों को मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ टिकैत ने कहा कि वो भाजपा को हराओ के नारे के साथ यू.पी. के मतदाताओं के पास भी जाएंगे।

उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि एम.एस.पी. हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा था। संयुक्त किसान मोर्चे में लगभग 40 किसान संगठन संघ शामिल हैं। राकेश टिकैत ने कहा केंद्र के

मतदाताओं के बीच जाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे राकेश टिकैत

राकेश टिकैत ने कहा कि, बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों के मुद्दे को सुलझा लें

लखनऊ, 25 नवम्बर भारतीय किसान यूनियन (बी.के.यू.) के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है। टिकैत एक साल से अधिक समय से दिल्ली के गाजीपुर सीमा से अधिक किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि एम.एस.पी. से किसानों को मदद मिलेगी। इसके साथ-साथ टिकैत ने कहा कि वो भाजपा को हराओ के नारे के साथ यू.पी. के मतदाताओं के पास भी जाएंगे।

उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि एम.एस.पी. हमेशा संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा था। संयुक्त किसान मोर्चे में लगभग 40 किसान संगठन संघ शामिल हैं। राकेश टिकैत ने कहा केंद्र के

■ उन्होंने आगे कहा कि, एम.एस.पी. हमेशा से संयुक्त किसान मोर्चा का मुद्दा था और रहेगा। केंद्र के साथ 11बार हुई बातचीत में हर बार हमने एम.एस.पी. पर चर्चा की। हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए।

■ इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। इन कानून को वापस लेने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र के दौरान इसे संसद में पेश किया जाएगा

साथ 11 दौर की चर्चा में हर बार हमने एम.एस.पी. पर चर्चा की। हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहिए और बातचीत शुरू

करनी चाहिए। टिकैत ने आगे कहा कि हम भाजपा हराओ नारे के साथ यू.पी. के मतदाताओं के पास जाएंगे। बेहतर होगा कि भारत सरकार और पी.एम. मोदी

आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) लागू होने से पहले इस मुद्दे को सुलझा लें।

टिकैत ने यह भी कहा कि बी.के.यू. समर्थकों को दिल्ली सीमा पर धरना स्थल को खाली करने की अभी कोई योजना नहीं है। टिकैत ने यह भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति भाजपा को पराजित करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे उनको गांवों में बायकॉट का सामना करना पड़े और चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। पश्चिम यू.पी. में यह पहले से ही शुरू हो चुका है। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। इन कानून को वापस लेने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र के दौरान इसे संसद में पेश किया जाएगा।

राजे की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विस्तार से चर्चा की जायेगी कि मोदी सरकार की लोक-कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेर के गांव, बगानों और घरों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बड़े आंदोलन होंगे, जिसकी शुरुआत मंडल स्तर से हो चुकी है। राजस्थान के हम सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि अमित शाह का हमें मार्गदर्शन मिले। हर महीने केंद्रीय वरिष्ठ नेता या केंद्रीय मंत्री का दौरा कानून को वापस लेने का ऐलान किया। इन कानून को वापस लेने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एक विधेयक को मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र के दौरान इसे संसद में पेश किया जाएगा।

भारत वैक्सिन खरीदने के लिए दो अरब डॉलर का ऋण लेगा

मनीला, 25 नवंबर (वार्ता)। एशियन डवलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण के वास्ते भारत को 1.5 अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया है।

ए.डी.बी. ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि इसके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से भी 50 करोड़ डॉलर का ऋण मिलने का अनुमान है। बयान में कहा गया है कि इस ऋण से भारत को कम से कम 66.7 करोड़ टीके के डोज खरीदने में मदद मिलेगी। इससे 31.7 करोड़ लोगों को टीके लगाये जा सकेंगे। इससे भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण प्लान को मदद की जायेगी जिसका उद्देश्य 18 वर्ष आयु से अधिक के 94.47 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। यह भारत की कुल आबादी का 68.9 प्रतिशत है। ए.डी.बी. के अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा ने कहा कि भारत को अपने नागरिकों को वैक्सीन लगवाने में इस लोन का उपयोग करेगा।

पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुंबई क्राइम ब्रांच के समक्ष प्रस्तुत हुये

क्राइम ब्रांच की टीम ने परमबीर सिंह से 7 घंटे पूछताछ की

मुंबई, 25 नवम्बर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह गुरुवार को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। इस दौरान उनसे सात घंटे तक पूछताछ हुई। क्राइम ब्रांच उनके खिलाफ जबरन वसूली के मामले की जांच कर रही है। परमबीर के वकील का कहना है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच के सामने बयान दर्ज कराया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, वह जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे।

राज्य सरकार के सूत्र ने बताया कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह छुट्टी पर थे और उन्होंने राज्य सरकार को अपने राज्य में लौटने की सूचना नहीं दी थी। राज्य सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। मुंबई पुलिस ने कहा कि परमबीर

■ सूत्रों के अनुसार पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह छुट्टी पर थे और उन्होंने राज्य सरकार को महाराष्ट्र वापस लौटने की सूचना नहीं दी थी। राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है।

सिंह ने अपराध शाखा इकाई 11 कार्यालय कांदिवली में बिमल अग्रवाल द्वारा दर्ज रंगदारी मामले में अपना बयान दर्ज कराया। उनसे इस मामले में ही सवाल पूछे गए थे। उन्हें अभी दोबारा नहीं बुलाया गया है, लेकिन कहा गया है कि जब भी जरूरत होगी उन्हें बुलाया जाएगा।

वहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सी.एम. अजीत पवार ने आज कैबिनेट बैठक के बाद अमरावती हिंसा और परमबीर सिंह के मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई। बैठक

में राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और गृह विभाग के अन्य आला अहिकारी मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बुधवार को खुलासा किया था कि वह चंडीगढ़ में हैं और जल्द ही मुंबई जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है इसलिए मैं यहां हूँ। वहीं पुलिस व कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैंने अभी अपने अगले कदम के बारे में निर्णय नहीं लिया

है। आई.पी.एस. अधिकारी परम बीर सिंह बुधवार शाम को टेलीग्राम में दिखे थे। हालांकि बाद में उन्होंने सोशल मैसेजिंग एप से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से स्थानांतरण और महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सिंह ने इस साल मई से काम करने की सूचना नहीं दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह से जांच में सहयोग करने को कहा था। कोर्ट ने फिलहाल परमबीर सिंह को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उनसे पूरे मामले की जांच के दौरान सहयोग बरतने का निर्देश दिया था। कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि परमबीर सिंह को पूरे मामले में फंसाया जा रहा है।

त्रिपुरा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गैंग घर-घर जाकर लोगों को डरा रही और घर से बाहर नहीं निकलने को कह रही है। मतदान 770 बूथों पर हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के गृह सचिव, राज्य चुनाव आयोग, और राज्य पुलिस प्रमुख से कहा है कि हरेक बूथ पर पर्याप्त मात्रा में सी.ए.पी.एफ. के जवान तैनात किए जाएं और कहा कि किसी भी आपात स्थिति में मतदान कर्मियों उनकी मदद ले सकते हैं। तुणमूल के एक पार्षद ने कहा था कि मतदान केंद्रों पर सी.सी.टी.वी. नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी है कि प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्बाध प्रवेश दिया जाए ताकि वे चुनाव का पूर्ण कवरेज कर सकें।

सत्तारूढ़ भाजपा, जो तुणमूल के साथ कोर्ट की टक्कर में है, 334 में से 112 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा में तुणमूल के कदम जमते हुए से लग रहे हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले एक ताकत के रूप में उभरने की कोशिश में है।

संधू के खिलाफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की थी। इसके अलावा तीनों अफसरों के खिलाफ भी कोई शिकायत नहीं है और ना ही उनका नाम एफआईआर में है। आवेदन में कहा गया कि ऐसे मामलों में अनावश्यक तौर पर अभियोजन का सामना करने से राज्य के अफसरों का मनोबल गिरेगा, जो जनहित में नहीं होगा। इसलिए इनके खिलाफ लिंबिट केस वापस लेने की अनुमति दी जाए। परिवर्तित रामशरण सिंह की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि "यह भ्रष्टाचार का गंभीर मामला है। एसीबी ने अनुसंधान कर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भी किया था, लेकिन अब एसीबी सरकार के इशारे पर केस वापस लेना चाहती है।" हाईकोर्ट भी संधू के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए पेश याचिका को खारिज कर चुका है। संधू के अमेरिकी जाने संबंधी प्रार्थना पत्र भी शुक्रवार को फैसला करेगी।

'शहीद हुए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किसान शुक्रवार को दिल्ली की सीमाओं पर पहुँचेंगे तथा इन सीमाओं पर अपनी ताकत के सफल शान्तिपूर्ण प्रदर्शन के जरिये सरकार को बाध्य करेंगे कि वह इन कृषि कानूनों को बिना किसी शर्त के रद्द करने के लिये सहमत हो जाये।

एक संयुक्त बयान में मोर्चा के नेताओं ने कहा कि इस आंदोलन के दौरान पिछले एक वर्ष में 683 किसान शहीद हो गये तथा केन्द्र को उदरगत दिखाते हुये, उनके परिवारों को हर्जाना देने के साथ ही उन्हें पुनर्वास उपलब्ध करानी चाहिये। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा सरकार को दिल्ली की किसी सीमा पर उनका स्मारक बनाने के लिये जमीन आवंटित करनी चाहिये।

मेघालय में एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेता के रूप में उभरने के उद्देश्य को अपने सामने रखकर, तुणमूल कांग्रेस प्रमुख बड़ी तेजी से इस दिशा में बढ़ रही हैं कि पार्टी के साइन बोर्ड बंगाल के बाहर, अन्य राज्यों में भी लगा जाये। पिछले दो दशकों से क्षेत्रीय दल के नेता के रूप में काम करने तथा सुस्थापित होने के बाद, बनर्जी ने अब तुणमूल कांग्रेस के पदचिन्ह पूरे भारत में पहुंचा देने का अपना एकमात्र ध्येय, इकलौता मिशन बना लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत की पहली लहर के जोश में आप नेता अरविन्द केजरीवाल ने भी इसी तरह से अपने उम्मीदवार सिंघिन पाटील, पंजाब और गुजरात शामिल हैं, में खड़े किये थे तथा उन्होंने स्वयं भी मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ा था। वे तो अपने प्रयासों में असफल

ताकि वह स्मारक उन शहीद किसानों की कुर्बानियों की याद दिलाता रहे।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि रिविचार को मुम्बई के आजाद मैदान के विशाल किसान-मजदूर महाप्रचलित आयोजित होगी, जिसमें 100 से अधिक संगठन भाग लेंगे। बयान में कहा गया है कि एस.के.एम. 27 नवम्बर को सिंधु सीमा पर अपनी मीटिंग करेगा, जिसमें आगे की कार्यवाही की रूपरेखा तय की जायेगी। यह संयुक्त बयान बलबीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शन सिंह, गौतम सिंह चरुनी, हार्दान मुल्ला, जगजीत सिंह डालीवाल, जोगिन्दर सिंह उग्रहान, शिव कुमार शर्मा 'काकाजी' यदुवीर सिंह तथा योगेन्द्र यादव के नाम से जारी किया गया है।

'बंटवारा खून की नदियां बहने से रोकने के लिए किया गया था, लेकिन कई गुना ज्यादा खून बह चुका है'

मोहन भागवत ने कहा कि, बंटवारे का दर्द तभी कम होगा जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन निरस्त होगा

नई दिल्ली, 25 नवम्बर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत-पाकिस्तान बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, अब खंडित भारत को अखंडित बनाना होगा। यह हमारा राष्ट्रीय एवं धार्मिक कर्तव्य है। हम इस कर्तव्य पथ पर चलेंगे तो विजय हमारी होगी। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहीं। वह सेक्टर-12 स्थित भाऊराव देवसर सरस्वती विद्या मंदिर में

आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। विद्यालय में आयोजित लोकार्पण समारोह में उन्होंने लेखक कृष्णानंद सागर द्वारा लिखित एवं जगुति प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'विभाजनकालीन भारत के साक्षी' का विमोचन किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का विभाजन न मिटने वाली वेदना है। यह तभी मिटेगी, जब विभाजन निरस्त होगा। भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं हमारी मातृभूमि है। संपूर्ण दुनिया को कुछ देने

लायक हम तब होंगे जब विभाजन हटेगा।

यह राजनीति नहीं हमारे अस्तित्व का विषय है। इससे किसी को सुख नहीं मिला। भारत की प्रवृत्ति विशिष्टता को अपनाते की है। अलगाव की प्रवृत्ति वाले तत्वों के कारण देश का विभाजन हुआ। हम विभाजन के दर्दनाक इतिहास का दोहराव नहीं होने देंगे।

आर.एस.एस. प्रमुख ने कहा कि कैसे देश टूटा, उस इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ना होगा। विभाजन के बाद भी

दंगे होते हैं। दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना जो खुद को सही लगे, यह गलत मानसिकता है। अपने प्रभुत्व का सपना देखना गलत है। राजा सबका होता है। सबकी उन्नति उसका धर्म है।

हिंदू समाज को संगठित होने की जरूरत है। हमारी संस्कृति विविधता में एकता की है, इसलिए हिंदू यह नहीं कह सकता कि मुसलमान नहीं रहेंगे। अनुशासन का पालन सबको करना होगा। अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी जन्नत की जगह भारत में

दोबारा जन्म की चाह रखते थे। अत्याचार को रोकने के लिए बल के साथ सत्य आवश्यक है।

लेखक कृष्णानंद सागर ने कहा कि उनकी पुस्तक विभाजन के दौर में हुए षड्यंत्रों पर आधारित है। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शंभू नाथ श्रीवास्तव ने कहा कि इतिहास को बदलकर प्रस्तुत किया गया है। विभाजन के दौर में भारी नरसंहार हुआ। इसके लिए पाकिस्तान पर मुकदमा होना चाहिए।